

खंभे से टकराई एम्बुलेंस,एक ही परिवार के 4 की मौत

5 घायल, सभी बिहार के रहने वाले, आंध्र प्रदेश से यूपी जा रहे थे

सिवनी (नप्र)। सिवनी में राहगीर को टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस खंभे से टकरा गई। इसके बाद सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। मृतकों में 3 साल का बच्चा शामिल है। एक्सीडेंट रविवार सुबह करीब 9 बजे जबलपुर रोड पर धारपाठा गांव के पास हुआ।

लखनाऊन थाना प्रभारी केपी धुर्वे ने बताया कि एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश के कूरनूल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी। इसी दौरान धूमा के धारपाठा गांव के पास झड़वर का नियंत्रण हट गया। एम्बुलेंस ने पहले पैदल जा रहे एक राहगीर को



टक्कर मारी, फिर अनबैलेंस होकर खंभे से टकरा गई। इसके बाद सड़क से उतर गई। टीआई धुर्वे ने कहा, एम्बुलेंस में 8 लोग सवार थे। जिनमें से प्रतिमा देवी, मुकेश और प्रिंस (3)

की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुनील शाह ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है।

हादसे में इनकी मौत हुई

प्रतिमा देवी पति लाल शाह (35) निवासी- बेतिया, बिहार
प्रिंस कुमार पिता लाल शाह (4) निवासी- बेतिया, बिहार
मुकेश शाह पिता दीपलाल शाह (36) निवासी- रक्सौल, बिहार
सुनील पिता मदन शाह (40) निवासी- गोकुल, बिहार

कान्हा टाइगर रिजर्व का बाघ 400किमी दूर छत्तीसगढ़ पहुंचा

टी-200 ने छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व को बनाया नया ठिकाना

मंडला (नप्र)। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व का एक बाघ 400 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इस खबर से बाघों के आवास को जोड़ने वाले कॉरिडोर की जीवंतता प्रकट होती है। ऐसे कॉरिडोर बाघ सहित अन्य वन्यप्राणियों के स्वच्छंद विचरण के साथ संरक्षण में सहायक होंगे।

कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने बताया कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरों में एक नया बाघ स्पॉट हुआ। जिसके बाद उन्होंने एनटीसीए में बाघ की आईडी जनरेट करने की कार्रवाई की। जहां



इसकी पहचान कान्हा के बाघ टी 200 के तौर पर हुई। यह बाघ कान्हा के कैमरों में जनवरी-फरवरी में ट्रैप हुआ था और उसके बाद इसकी आईडी जनरेट हुई।

उन्होंने बताया कि टी 200 बाघ के अब

अचानकमार में देखे जाने से ये लगता है कि डिंडोरी, मंडला के वन क्षेत्र को सम्मिलित कर जो टाइगर कॉरिडोर चिन्हित किया गया है, वन्य प्राणी उसका उपयोग कर रहे हैं। इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिससे आगे भी ये मूवमेंट बना रहे। डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने इन कॉरिडोर की उपयोगिता के सवाल पर कहा कि कॉरिडोर से जब कोई प्रजाति एक से दूसरे क्षेत्र में जाती है तो जीन फ्लो होता है। इस जीन ड्राइवर्सिटी से जेनेटिक में फायदा होगा। जलवायु परिवर्तन या कोई बीमारी फैलती है तो जितनी जेनेटिक विविधता होगी प्रजाति के उत्तनी ही अधिक बचे रहने की संभावना रहेगी।

संक्षिप्त समाचार

पंजाब में ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए मिलेंगे 666.81 करोड़

- जम्मू-कश्मीर जाने वाले लोगों को फायदा,1 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने पंजाब में ग्रीनफील्ड पठानकोट लिंक रोड के निर्माण के लिए 666.81 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 12.34 किलोमीटर लंबी यह सड़क एनएच-44 पर स्थित तलवाड़ा जट्टों गांव को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर स्थित गोबिंदसर गांव से जोड़ेगी। यह जानकारी खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन



गडकरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि हमने हाईवे के लिए राशि मंजूर कर दी है। इस हाईवे के बनने के बाद एक घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। साथ ही पठानकोट के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा। पठानकोट लिंक रोड 4/6 लेन का होगा। यह एनएच-44 (दिल्ली-श्रीनगर), एनएच-54 (अमृतसर-पठानकोट) और जम्मू-कश्मीर में निर्माणाधीन दिल्ली अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे (पैकेज 14) के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टर के रूप में काम करेगा।

गौतम अडानी बोले

साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है

- पुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाईं,बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया

जयपुर (एजेंसी)। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिव्रत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप के रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, दुनिया उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा लेती है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाईं, बल्कि



उन्होंने हमें और मजबूत बनाया। हमारे अंदर ये भरोसा बढ़ाया कि हर गिरावट के बाद हम और मजबूत तरीके से ऊपर उठेंगे। गौतम अडानी शनिवार शाम को जयपुर में 51वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवॉर्ड समारोह में बोल रहे थे। साल 2010 में जब हमने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग शुरू की थी, तो हमारा उद्देश्य था कि हमें भारत को एनर्जी सेक्टर में और मजबूत करना है। हमारा उद्देश्य था कि भारत में होने वाले 2 टन खराब कोयले को ऑस्ट्रेलिया से 1 टन अच्छी क्वालिटी के कोयले से रिप्लेस करेंगे। हालांकि गैर सरकारी संगठनों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और ये 10 साल तक चला।



मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के विकास कार्यों की समीक्षा की।

केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया वैदिक घड़ी का अवलोकन

भारतीय कला परम्परा को पुर्नसमर्थन देने की जा रही है मूर्ति कार्यशालाओं की स्थापना : मुख्यमंत्री

भोपाल/उज्जैन (नप्र)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने उज्जैन प्रवास के दौरान रविवार शाम को आचार्य वराहमिहिर वेधशाला, जंतर मंतर स्थित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा को बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कला गणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा को वैदिक घड़ी की गणना का साहित्य भी भेंट किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और सांसद श्री शर्मा ने महदेव मूर्ति शिल्प कार्यशाला का भ्रमण भी किया। उन्होंने राजस्थान के बंसी पहाड़ से लाए गए पत्थर से बनी महर्षि जमदग्नि की 12 फीट ऊंची,10 फीट चौड़ी और 4.5 फीट मोटाई की शिल्पियों द्वारा निर्मित की जा रही मूर्ति



का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने ओडिशा के शिल्पकार श्री ईश्वरचंद से चर्चा भी की। शिल्पकार ने बताया कि महर्षि जमदग्नि की यह पाषाण प्रतिमा 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस कार्यशाला में उड़ीसा, राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के शिल्पकार कार्य कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजन अनुरूप जिले में मूर्तिशिल्प निर्माण की कार्यशाला सक्रिय हुई है। इससे उज्जैन एवं आस-पास के अंचल में शिल्प निर्माण में रुचि रखने वाली प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन ने निर्णय किया है कि विश्व में मान्य भारतीय कला परम्परा को पुनर्समर्थन देने, पारंपरिक भारतीय प्रतिमा विज्ञान के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालिक मूर्ति कार्यशालाओं की स्थापना की जाए।

सीएम की पहल पर माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित

प्रदेश का आठवाँ टाइगर रिजर्व होगा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रदेश का आठवाँ टाइगर रिजर्व होगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-जीव) श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि एनटीसीए की तकनीकी समिति ने प्रस्तावित बाघ अभयारण्य का कोर क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र 1276 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 1751 वर्ग



किलोमीटर होगा। समिति ने राष्ट्रीय उद्यान में एक नर और एक मादा बाघ को छोड़ने की भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था।

श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गयी संरक्षण पहल माधव राष्ट्रीय उद्यान और कूनी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य-जीव प्रबंधन को मजबूत करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को अपेक्षित ईको-टूरिज्म का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

हिंदू और तिरंगे के सम्मान में, अब डॉक्टर मैदान में

कोलकाता में बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से किया इनकार

कोलकाता (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कुछ डॉक्टरों ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। कोलकाता के माणिकतला स्थित जेएन रे अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार और भारतीय ध्वज के अपमान को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया है। अस्पताल के एक अधिकारी सुभांशु भक्त ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, हमने एक नोटिस जारी किया है कि



द्वारा भारत के प्रति दिखाए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण लिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कोलकाता के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से भी इस तरह के कदम उठाने की अपील की है।

बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलाम करें, तभी इलाज होगा

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में कुछ डॉक्टरों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगाया है। डॉक्टर ने झंडे के साथ मैसेज में लिखा- भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी मां की तरह है। कृपया वैंबर में एंटी करने से पहले तिरंगे को सलाम करें। खासकर बांग्लादेशी मरीज, अगर वे सलाम नहीं करते हैं, तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा।

देश के सारे मुसलमान पहले हिंदू थे : नियाज खान आईएसएस



अफसर नियाज खान ने एक मीडिया संस्थान के इंटरव्यू में कहा कहा, मंदिरों से मुसलमान बच्चों का भला नहीं होगा, देश के सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, 1000 साल पहले बाहर से आये सबको मुसलमान बना दिया, सारे वेद मैंने पढ़े हुये हैं, मुझे फतवों से डर नहीं लगता, देश संविधान से चलता है।

मैं केवल देश का कानून मानता हूं। इतिहास उठाकर देखो। जिसने ब्राह्मणों को खूंस करने की कोशिश की वो खुद खूंस हो गया। ब्राह्मण अमर हैं। वह गिर के फिर उसी ताकत से उठ जाता है , तभी तो धर्म बचा हुआ है।

नहीं थम रही हिमंता और सोरेन के बीच अदावत

गुवाहाटी (एजेंसी)। झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हेमंत सोरेन पर खूब निशाना साधा था लेकिन चुनावी नतीजे के बाद अब भी दोनों नेताओं के बीच खींचतान जारी है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह झारखंड में कुछ चीजों का



- झारखंड में 'स्टडी' के लिए दो टीमें भेजेगेंगे असम सीएम

लिए असम सरकार के लिए चिंता के क्षेत्रों का जिक्र नहीं किया। बिस्वा सरमा ने कहा, 5 दिसंबर को हमारी कैबिनेट में हम झारखंड के कुछ इलाकों के दौर को लेकर कुछ फैसले लेंगे। हम भी जाएंगे और वहां दो-तीन चीजें देखेंगे। 28 नवंबर को जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही उनकी सरकार ने असम में कथित तौर पर हाशिए पर चाय जनजातियों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए एक पैनल के गठन को मंजूरी दे दी थी।

राज्यपाल पटेल से बिहार के राज्यपाल आर्लेकर ने की सौजन्य भेंट

● विकास के विभिन्न विषयों पर हुई अनौपचारिक चर्चा



भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में में आज शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों प्रदेशों के राज्यपालों ने परस्पर विकास के विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक चर्चा की। राज्यपाल श्री पटेल ने बिहार के राज्यपाल श्री आर्लेकर का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। राज्यपाल श्री पटेल का बिहार के राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अंग वस्त्र एवं स्मृति प्रतीक भेंटकर अभिनंदन किया।

प्रदेश को 9 नए आईएसएस मिले

● यूपीएससी ने परिणाम के बाद किया कैडर अलॉट, अब मप्र में आईएसएस की संख्या बढ़कर हो गई 393

भोपाल (नप्र)। लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा वर्ष 2023 में जारी किए गए परिणाम के बाद अब अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया गया है। कुल 180 अफसरों में से 9 अफसरों को मप्र कैडर मिला है। इनमें 3 आईएसएस छाया सिंह, आकाश अग्रवाल और कुलदीप पटेल मप्र के ही रहने वाले हैं। छाया सिंह आईएसएस छोट्टे सिंह की बेटी हैं। बाकी 6 में से 4 आईएसएस महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, 1 राजस्थान और एक उप्र के रहने वाले हैं। इन 9 को मिलाकर मप्र में अब कुल 393 आईएसएस अफसर हो गए हैं। नवंबर में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई प्रेडेशन लिस्ट में 385 आईएसएस अफसर थे, लेकिन इस महीने 1990 बैच के आईएसएस अफसर मलय श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके रिटायर होने के बाद 384 और नए 9 आने के बाद बढ़कर संख्या 393 हो गई है। गौरतलब है कि बीते साल भी कुल 9 आईएसएस अफसरों को मप्र कैडर मिला था।

मुख्यमंत्री ने दी सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लिखा है कि जीवन पर्यंत कर्तव्य के वाक्य को चरितार्थ करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान, विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा को समर्पित हैं। साहस, शौर्य, सजगता एवं समर्पण के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछर कर दिया, उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पूरे प्रदेश में हो कार्यक्रम : मंत्री कुशवाह

भोपाल (नप्र)। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पूरे प्रदेश के दिव्यांगों की क्षमताओं और उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए एक समवेशी समाज के निर्माण में प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कार्यक्रम किये जाये। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि सुगम भारत अभियान के अंतर्गत हम सबको मिलकर सुगम वातावरण निर्माण और आईटीसी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का कार्य करना चाहिए इससे दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पर दिव्यांगजनों के कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। ऐसे आयोजनों से न केवल समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जनता को सुगमता के महत्व के प्रति हम जागरूक भी कर सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हमारी समाज के इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाला दिवस है। दिव्यांगजन, समाज की मुख्य धारा से जोड़कर आगे लाना और उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना हम सब का दायित्व है।

सीएम यादव प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

- मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर होगी साबित
- उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सफल विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री को दी बधाई

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की और उनके सफल ब्रिटेन एवं जर्मनी दौरे के लिए बधाई दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह दौरा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है।



उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि, बिजली और कर संबंधी सुविधाएं दी हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और उद्योग हब विकसित किए हैं। हर क्षेत्र के विकास के लिए वहां की विशेषताओं और क्षमता का पूरा उपयोग करने की रणनीति बनाई है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विश्वास जताया कि यह यात्रा मध्यप्रदेश में निवेश का नया युग शुरू करेगी। यह प्रदेश की अद्वितीय विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश समग्र विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में क्षेत्रीय क्षमताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियां लागू की हैं और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को प्राथमिकता दी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश आज निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है। हमने न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है, बल्कि प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को रोजगार के नए अवसरों में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रदेश की प्रगति को नया आयाम देगा और युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित करेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के विभिन्न निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। निवेशकों ने मध्यप्रदेश की प्रगतिशील नीतियों, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और उद्योगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की।

मौलाना जमशेद बोले- दीन का काम एक इबादत

इज्तिमा में मौलाना सईद ने कहा- अपने किरदार से इस्लाम का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं



भोपाल (नप्र)। भोपाल में आलमी तब्त्नीगी इज्तिमा के तीसरे दिन रविवार को इज्तिमा गाह पर उलेमाओं ने दीन की मजलिसों में ताकीद की। अल सुबह फजिर की नमाज के बाद उलेमाओं के बयान शुरू हुए। मौलाना जमशेद ने कहा- दीन का काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक इबादत है, जो ईसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। मौलाना सईद ने बताया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजबब नहीं, बल्कि यह ईसानी जिंदगी के हर पहलू को संभालने वाला मजबब है। मुसलमान अपने किरदार से इस्लाम का सच्चा संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। मौलाना मंजर तौहीद और इखलास ने कहा कि मुसलमानों को हर समय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सभी कामों में उसकी रज़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आज दुआ के साथ समापन होगा

चार दिन के इज्तिमा का समापन सोमवार सुबह दुआ-ए-खास के साथ होगा। दुआ के लिए सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्र किया गया है। सुबह फजिर की नमाज के बाद मौलाना सआद साहब का खास बयान होगा। इस दौरान वे जमातों में निकलने वाले लोगों को इस सफर में अपनाए जाने वाले अखलाक, रखे जाने वाले ख्याल और किए जाने वाले काम समझाएंगे। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे दुआ होगी। जिसके बाद लोग इज्तिमागाह से रुखसत होना शुरू हो जाएंगे। इज्तिमा प्रबंधन ने बताया कि दुआ के बाद इज्तिमा से करीब 2 हजार जमातें देशभर के लिए निकलेंगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भाजपा बीजेपी संगठन को दी बधाई, एक्स पर लिखा-

नवाचारों के साथ 100 प्रतिशत बूथों का डिजिटलाइजेशन बना आदर्श

भोपाल (नप्र)। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी में इंदौर और उज्जैन दौरे से पहले एमपी के संगठन को बधाई दी है। नड्डा ने कहा है कि नवाचारों के जरिये संगठन के रचनात्मक कार्यों को धरातल पर उतारकर आदर्श स्थापित करने का काम किया गया है। नड्डा की बधाई पर सीएम डॉ मोहन यादव ने उनका आभार माना है, साथ ही बीजेपी एमपी संगठन को भी बधाई दी है।



केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने एक्स पर किए ट्वीट में कहा है कि, संगठन पर्व के अंतर्गत एमपी बीजेपी संगठन ने सदस्यता अभियान में बूथ समिति निर्माण के साथ 100 प्रतिशत बूथों का डिजिटलाइजेशन कर नई उपलब्धि हासिल की है। नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संचालित यह अभियान मंडल, जिला और राष्ट्रीय स्तर तक नए आयाम स्थापित कर रहा है। निश्चित रूप से संगठन पर्व हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 'विकसित भारत' निर्माण के संकल्प की सिद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। विभिन्न नवाचारों के जरिए

ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में बजरंग दल का हंगामा

भोपाल में धर्मांतरण का लगाया आरोप; पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने हाथ पकड़कर रोका

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक घर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाने लगी।



इस दौरान जिस युवक पर धर्मांतरण का आरोप लगा है, उसे पकड़े जाने पर महिलाओं ने विरोध किया और बहस करते हुए पुलिसकर्मी का हाथ पकड़कर रोक दिया। बाद में दोनों पक्ष थाने गए और अपने-अपने दावे करने लगे। मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर का है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उनके पास से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किए जाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। जिसमें प्रभु ईशा मसीह और ईसाई धर्म से जुड़ी बातें लिखी हैं। टीआई अमित सोनी ने बताया-अभी दोनों पक्षों को सुना जा रहा। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे।बाग सेवनिया थाने पहुंची महिलाओं ने कहा कि धर्मांतरण के सभी आरोप गलत हैं। बजरंग दल के भेल एरिया प्रमुख भगवान सिंह परमार ने बताया- शिवांकर नाम के युवक के घर में पिछले 6 महीने से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रार्थना के बहाने बुलाया जा रहा था। सभी प्रार्थना के बहाने लोगों को

केबीटी कन्वेंशन सेंटर को अपग्रेड करने को 99.39 करोड़ मंजूर

बैंक्रेट हॉल, एग्जीबिशन एरिया, बिजनेस सेंटर होंगे सर्वसुविधायुक्त

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे (केबीटी) कन्वेंशन सेंटर को इंटरनेशनल लेवल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 99.38 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। वहीं ओरछा में टूरिस्ट सुविधाएं जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। एमपी टूरिज्म बोर्ड के प्रस्ताव पर करीब 200 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्र से मिली राशि से 'केबीटी' कन्वेंशन सेंटर में बैंक्रेट हॉल, देश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एग्जीबिशन एरिया, बिजनेस सेंटर, बैंक्रेट हॉल सहित आधुनिक तकनीक से युक्त सर्व सुविधाओं का विकास किया जाएगा।



एमआईसीई की कैटेगिरी अनुसार तैयार होगा

एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) के मानकों के अनुरूप कन्वेंशन सेंटर को अपग्रेड कर विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बैंक्रेट हॉल सहित मीडिया सेंटर, बिजनेस सेंटर भी बनेंगे।

मिटो हॉल से केबीटी कन्वेंशन सेंटर हुआ था: करीब 3 साल पहले मिटो हॉल का नाम बदला गया था। इसकी नींव 115 साल पहले वर्ष 1911 में रखी गई थी। इसे बनने में 24 साल लग थे। मिटो हॉल मध्यप्रदेश के बनने से लेकर पहली सरकार के गठन तक का साक्षी रहा है। पहली सरकार ने शपथ इसी हॉल में लिया था। भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। पुरानी विधानसभा रहे मिटो हॉल में कई सेलिब्रिटी आ चुकी हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ कर चुकी हैं। सरकार हॉल में विभिन्न आयोजन करती है। यही हॉल अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जा रहा है और अब इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा।

भोपाल से गोवा के लिए नई उड़ान शुरू

हफ्ते में 6 दिन चलेगी फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जल्द कनेक्टिविटी बढ़ाएगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से गोवा के लिए नई सीधी उड़ान सेवा 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई-366 अब गोवा के डबोलिम एयरपोर्ट से दोपहर 1 बजे प्रस्थान करेगी और भोपाल हवाई अड्डे पर दोपहर 2ः50 बजे पहुंचेगी। वहीं, फ्लाइट संख्या 6ई-367 भोपाल से दोपहर 3ः20 बजे प्रस्थान कर गोवा के डबोलिम हवाई अड्डे पर शाम 5ः10 बजे पहुंचेगी। इस नई उड़ान का शुभारंभ सांसद (लोकसभा-भोपाल) आलोक शर्मा ने रविवार को भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत कर किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भोपाल ने इस उड़ान का स्वागत वाटर केनन सलामी देकर किया। इस अवसर पर विमानपत्तन निदेशक श्री रामजी अवस्थी सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी यह फ्लाइट: यह नई उड़ान सेवा सप्ताह में रविवार से शुक्रवार तक (6 दिन) संचालित होगी, जिससे यात्रियों को गोवा और भोपाल के बीच सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। गोवा, इस शीतकालीन सत्र (27 अक्टूबर से प्रभावी) में भोपाल से जुड़ने वाला पुणे और रीवा के बाद तीसरा नया गंतव्य बन चुका है।

भोपाल से सीधे 12 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट: भोपाल एयरपोर्ट अब देश के 12 शहरों से, सीधी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु,

निगम परिषद की बैठक 7 दिसंबर से पहले संभव

अध्यक्ष सूर्यवंशी बोले- त्योहार की वजह से संभव नहीं था; कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है

भोपाल (नप्र)। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग की तारीख तय नहीं होने से सियासत गरमा गई है। कांग्रेसी पार्षद 'शहर सरकार' पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। नियमों का हवाला देते हुए वे भोपाल कमिश्नर संजीव सिंह से शिकायत भी कर चुके हैं। इसी बीच निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि त्योहार की वजह से मीटिंग संभव नहीं हो पाई। कांग्रेसी पार्षद सिर्फ राजनीति करते हैं। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया, मीटिंग का एजेंडा तय कर रहे हैं। इस सप्ताह मीटिंग कर लेंगे। यानी, 7 दिसंबर से पहले निगम परिषद की मीटिंग हो जाएगी।कांग्रेसी पार्षदों ने हाल ही में कमिश्नर संजीव सिंह को आवेदन सौंपकर निगम परिषद



की मीटिंग जल्द कराने की मांग की थी।

2 महीने में होनी चाहिए थी, 3 महीना बीता: इधर, नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि परिषद की पिछली मीटिंग 2 सितंबर को हुई थी। नियमानुसार अगली मीटिंग 2 नवंबर को होनी चाहिए थी, लेकिन अब 30 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। इसके बावजूद न तो मीटिंग की तारीख तय हुई है और न ही कोई एजेंडा सामने आया है। यह नियमों का उल्लंघन है।

पहले मदद करते थे, फिर नौकरी का झांसा देते हैं

बजरंग दल के मुन्ना लाल साहू ने बताया कि शिवांकर और उसके साथी भाऊ नाम के एक व्यक्ति के परिवार को परेशान कर रहे थे। पहले उसके बच्चे के इलाज कराने में मदद की गई। बाद में उन्हें अच्छे पढ़ाने और नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया। इसके बाद उन्हें खर्च की रकम भी दी जाने लगी। अब उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। जिसकी शिकायत भाऊ ने बजरंग दल से की थी। उनकी शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है।महिला ने कहा कि जब हमारे बच्चे बिगड़े थे तो कोई नहीं हमारी मदद करने आया।

महिला बोली- पहले मदद करने तो नहीं आए

बाग सेवनिया थाने पहुंची एक महिला गीता बाई ने कहा कि जब हमारे बच्चे बिगड़े थे तो यही बाग सेवनिया थाने वाले उन्हें पकड़कर ले जाते थे। हमने 10-10 हजार रुपए देकर उन्हें छोड़ाया है। तब तो बजरंग दल वाले कोई हमारी मदद करने नहीं आया। क्या हम पागल रहे हैं। हमने पूरे होशो-हवास में प्रभु को ग्रहण किया है। हम पीछे नहीं हटेंगे।

संपादकीय

जीडीपी की घटती रफ्तार चिंताजनक

देश में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) के दूसरी तिमाही के आंकड़े न केवल चिंताजनक हैं, बल्कि इसने उस महत्वाकांक्षा पर भी प्रश्न चिह्न लगा दिया है कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। यही हाल रहा तो दुनिया की तीसरी आर्थिकी बनने का सपना दूर की कौड़ी सिद्ध होगा। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसी साल जुलाई में जारी जीडीपी के आंकड़ों अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीदें जगाने वाले थे। ऐसे में आर्थिकी में आई इस सुस्ती के कारणों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। गौरतलब है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 प्रति. रह गई। जो दो साल में इसका सबसे निचला स्तर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक आर्थिकी की रफ्तार में यह सुस्ती विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन की वजह से आई। इसके अलावा बढ़ती मंहगाई और ऊंची ब्याज दर भी प्रमुख कारण हैं। शेंयर बाजार में भी बड़ी गिरावट आई। इससे विदेशी निवेशक भी भारत से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। देश में कर्मचारियों के वेतन में भी उल्लेखनीय इजाफा नहीं हुआ, जिससे खपत को बढ़ावा नहीं मिला। इसे देखते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों ने आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती करने की अपील की है। इससे कर्ज लेना सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। अब आरबीआई क्या कदम उठाती है, यह देखने की बात है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनियों के नतीजे भी बेहद ध्यान रहे कि जीडीपी एक निश्चित अवधि में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बताता है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कुछ क्षेत्र की वृद्धि दर पिछली तिमाही में 3.5 प्रति. हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 1.7प्रति. थी। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.2 प्रति.पर आ गई जो पिछले साल की समान अवधि में 14.3 प्रति. की दर से बढ़ा था। पिछली तिमाही में ‘खनन और उत्खनन’ क्षेत्र का जीवौए भी बड़ी गिरावट के साथ 0.01 प्रतिशत पर आ गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 11.1 प्रति. बढ़ा था। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.3 प्रति. थी। संतोष की बात यही है कि आर्थिकी वृद्धि की सुस्त रफ्तार के बाद भी दुनिया में भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जुलाई-सितंबर तिमाही में चीन को जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6 प्रति. था। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमानों की तुलना में यह ग्रोथ रेट काफी कम है। ईटी के एक सर्वे में 17 अर्थशास्त्रियों ने इसके 6.5 प्रति. रहने का अनुमान जताया था जबकि रायटर्स के एक पोल में भी यह बात सामने आई थी। आरबीआई ने 7 प्रति. का अनुमान जताया था। उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत अगले तीन साल में 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन सकता है। लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़ों से इन अनुमानों को झटका मिला है। दूसरी तिमाही में कंपनियों के कमजोर नतीजों ने नए निवेश और विस्तार योजनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसे अर्थव्यवस्था के खतरे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ बेहतर रह सकती है। क्योंकि आरबीआई ने इस साल के प्रारंभिक वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत रहने के अनुमान जताया है। इसके लिए अर्थव्यवस्था को दूसरी छमाही में काफी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर आरबीआई अगली एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती करता है, तो खपत को बढ़ावा मिल सकता है। इसका असर जीडीपी ग्रोथ पर भी दिख सकता है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।



कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार आए हैं कि श्सब-अर्बन ट्रेनों को रेल-नेटवर्क से अलग करके राज्यों को सौंपने का प्रस्ताव नीति आयोग की ओर से सरकार के पास पहुंचाया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार रेलवे की माली हालत सुधारने के लिए यह आवश्यक है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इंएमयू-डीएमयू सहित 200 किलोमीटर तक चलने वाली लोकल रेल गाड़ियां राज्य सरकारों को दी जा सकती हैं। यद्यपि इनका परिचालन रेलवे के अधीन रहेगा तथा रेलों के फेरे, किराया, स्टॉपिज आदि राज्य सरकार तय कर सकेंगी। नीति आयोग ने इस प्रस्ताव का आधार रेलवे की जर्जर आर्थिक स्थिति को बताया है और यह प्रचार निरंतर रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है कि यात्री किराए में 56 प्रतिशत अनुदान रेलवे देता है।

यह प्रचार है कि भारतीय रेल घाटे में है और सरकार 56 प्रतिशत अनुदान दे रही है। मात्र नीति आयोग के प्रस्ताव का ही नहीं, यह प्रचार रेलवे अपने टिकटों के पीछेपिछले कई वर्षों से निरंतर छाप कर भी कर रही है। टिकट के पीछे लिखा जाता है कि क्या आपको पता है कि अफिक टिकट में 56 प्रतिशत का अनुदान है? हालांकि हमारा समाज इतना सहनशील हो चुका है कि वह इस झूठ के प्रति विरोध तो दूर की बात कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करता। हालांकि, कभी भी रेलवे ने या नीति आयोग ने इस जानकारी के विवरण को प्रकाशित नहीं किया कि आखिर यह 56 प्रतिशत घाटा, जो रेलवे को हो रहा है, उसका आधार क्या है? जबकि, वर्तमान यात्री किराए से लगभग 40 से 50 प्रतिशत कम किराए पर यात्री रेलगाड़ियां चलती रही हैं। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद यात्री किराए में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि सामाजिक दायित्व के आधार पर जो सुविधा यात्रियों के विभिन्न वर्गों को मिलती थी उन्हें भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। 2014 के पहले वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में 40 प्रतिशत तक की छूट थी, महिलाओं को तो 50 प्रतिशत तक की छूट थी और इसी प्रकार अन्य कई श्रेणी के यात्रियों को भी यात्री किराये में छूट मिलती थी। इन रियायतों को रेलवे ने बंद कर दिया। कोरोना काल का बहाना बनाकर भारत सरकार ने जो रियायतें बंद करने के निर्णय लिए थे उन्हें फिर शुरू भी नहीं किया। यद्यपि कोरोना काल भी समाप्त हो गया। मतलब साफ़है कि कोरोना सरकार के लिए एक बहाना मात्र ही था।

कोरोना काल में ही सरकार ने टिकटों के निरस्तीकरण(रद्द करने) की दंरं भी काफी बढ़ा दी थी। अब स्थिति यह है कि स्लीपर क्लास के टिकट को कैसिल (रद्दिनरस्त) करने पर न्यूनतम 65 रुपया कटता है, एसी 3 टीयर का 120 रुपया कटता है और अन्य उच्च श्रेणी का तो 200 रुपया तथा कुछ गाड़ियों में तो लगभग आधा पैसा कट जाता है।

जबकि गाड़ियों में इतनी भीड़ है कि दो-दो तीन-तीन माह तक यात्री गाड़ियों में आरक्षण नहीं मिलता और कोई सीट खाली भी नहीं जाती। यानि अगर एक टिकट निरस्त होता है तो दूसरे 10 उसको लेने वाले खड़े रहते हैं। रेलवे के लिए यह निरस्तीकरण मुनाफे का धंधा हो गया है। अगर नीति आयोग या रेलवे इसका आंकड़ा जारी करें कि पूरे देश में टिकटों के निरस्तीकरण से उसे कितनी कमाई हुई है तो यह राशि अरबों रूपयों में पहुंचेगी।

ब्रिटिश काल से यात्रियों को श्रेक-जर्नीय की सुविधा दी जाती थी। पहले तो 300 किलोमीटर पर श्रेक-जर्नीय मिलती थी, फिर 500 किलोमीटर पर हुई और अब उसे बंद ही कर दिया गया है। इस सुविधा को बंद करके भी रेलवे अरबों रुपयों का मुनाफ़ा कमा रही है। गरीब-रथ के नाम पर जो मजाक हुआ था, उसे कौन भूल सकता है और कुछ गरीब रथों में तो शायिकायों की संख्या एक बोगी में बढ़कर 80 कर दी गई थी। जिसका परिणाम हुआ था कि साइड लोअर, साइड मिडल और साइड अपर शायिका (बर्थ) का यात्री ना बैठ सकता था और ना ही सो सकता था। बेड-रोल के पैसे अलग लिए जाते हैं यानि एक अर्थ में किराया कम नहीं हुआ था बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाकर रेलवे की कमाई में वृद्धि की गई थी। अब वर्तमान सरकार ने भी एसी3 टीयर में एक नई इकोनॉमी क्लास शुरू की है, जिसकी बोगी में सीटों की संख्या 72 से बढ़कर 80 से 90 के बीच कर दी है। किराए में कमी मात्र 50 रुपये की है परंतु दो शायिकायों के बीच का अंतर इतना कम कर दिया है कि यात्री पांच फैंलाकर भी नहीं बैठ सकता। दरवाजे के पास जो स्थान अटेंडेंट और बैड-रोल आदि रखने के लिए रखा जाता था, उसे खत्म कर दिया है। हालत यह हैकि बोगी के प्रवेश द्वार पर बेड-रोल के बड़े-बड़े बंडल पड़े रहते हैं तथा यात्रियों को इससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। शताब्दी ट्रेन का किराया तो बढ़ा ही है। परंतु, बोगियों की हालत बदतर हो गई है। 45 वर्ष पूर्व की बोगियां यानि शताब्दी जब बनी थी उन्ही बोगियों में आज भी यात्री यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेन को अपनी प्रिय गाड़ी घोषित किया है परंतु उसका किराया शताब्दी से भी लगभग डेढ़ गुना ज्यादा है।

यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि अब वंदे भारत गाड़ियों में स्लीपर लगाकर स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जायेंगी। परंतु, इनका किराया कितना होगा यह आने पर ही मालूम होगा। यह बहुत प्रचार किया जाता है कि वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम गति 200 कि.मी.ध टूटा की है। दरअसल, यह 200 कि.मी.ध्वंटे की गति नहीं है बल्कि गति की अधिकतम क्षमता है। परंतु, वह चलती इस रफ्ता से है यह भी समझना होगा!! वंदे भारत भोपाल से नई दिल्ली आने में 7 घंटे 36 मिनट का समय लेती है और शताब्दी एक्सप्रेस 8 घंटे 25 मिनट तथा

राजधानी एक्सप्रेस 8 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस के समय के बीच 49 मिनट का फर्क है। परंतु, वंदे भारत के स्टॉपिज भोपाल से दिल्ली के बीच मात्र तीन हैं-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर तथा आगरा कैट। जबकि शताब्दी एक्सप्रेस के स्टॉपिज बढ़कर अब 9 कर दिए गए हैं। अगर एक स्टेशन पर ट्रेन 2 मिनट भी रूकती है तो गति को कम करने और फिर से गति को पकड़ने में 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं। कुछ जगह तो 10 मिनट तक भी लग जाते हैं। अगर आप औसत 7 मिनट भी मान लें तो 9 स्टॉपिज के 63 मिनट होते हैं। जबकि वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस के बीच पहुंचने का अंतर मात्र 49 मिनट है यानी अगर शताब्दी के भी उतने ही स्टॉपिज हो जितने बंदे भारत के या वंदे भारत के भी उतने ही स्टॉपिज हों तो वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस से लगभग 14 मिनट ज्यादा समय लेगी। यह भारत सरकार के हाई स्पीड ट्रेनों की गति की असत्यलियत है। वंदे भारत अगर 200 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार चलती है तो उसे दिल्ली पहुंचने में मुश्किल से 3.30 घंटे का समय लेना चाहिए। परंतु, वंदे भारत 705 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे 36 मिनट लेती है यानि लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा और शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग, ऐसी ही रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस भी चलती है। अब प्रधानमंत्री जी की ड्रीम हाई स्पीड ट्रेन और कांस्रस के जमाने की शताब्दी एक्सप्रेस में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। बल्कि, कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि भारत सरकार के इशारे पर शताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे के तंत्र में उपेक्षित किया जाता है ताकि वंदे भारत को महत्वपूर्ण बनाया जा सके।

ऐसे भी समाचार आए हैं कि भारत अब स्वदेशी बुलेट ट्रेन जिसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी चलाने की तैयारी में है। इस योजना पर भारत सरकार 867 करोड़ रूपया 16 कोच बनाने पर खर्च कर रही है। यानि एक कोच की कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए होगी। जबकि, अभी जो कोच तैयार हो रहे हैं उनमें पैसेंजर गाड़ियों के डिब्बे तो 10 से 15 करोड़ में बन जाते हैं। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच भी 20 से 30 करोड़ में बन जाते हैं। इस सब चर्चा का निष्कर्ष यही है कि, सरकार कुछ नया नहीं कर पा रही है। व्यवहार में सरकार यात्रियों के लिए यात्रा की दूरी तय करने के समय में कमी नहीं कर पा रही है। सरकार बस किराया बढ़ाती है और प्रचार करती है। शंखचिल्ली के समान सरकार प्रचार करती है और पैसा कमाती है। इन नयी कल्पित योजनाओं से जिनमें सब अर्बन ट्रेनों को राज्यों को सौंपने का निर्णय किया जा रहा है। यह सही अर्थों में निजीकरण की ओर ले जा रहा है। देश की जनता को और रेल मजदूरों के संगठनों के नेताओं को इन संभावित खतरों को समझना चाहिए।

शिक्षा

प्रतीक्षा त्रिपाठी

नवाचारी शिक्षिका



प्रिय गिजुभाई जी, वैश्विक शिक्षा साहित्य की अमरकृति ‘दिवास्वन’ के स्वप्नकार को मेरा शत-शत नमन। मैंने आपकी कृति ‘दिवास्वन’ पढ़ी। क्या स्वप्न देखा आपने...सुखदा! आप तो सपनों के जादूगर हैं जो हर शिक्षक को स्वप्न देखना सिखा गए। रच गए ऐसी एक दुनिया जहाँ असंभव शब्द के कोई मायने ही नहीं, सब कुछ संभव है। कैसे और कब देखा आपने ये दिवास्वन जिसमें बच्चे अपने सपनों का संसार खोज सकें, अपनी कल्पनाओं को साकार कर सके। काश ! मैं मिल पाती आपसे तो पूछ पाती कि विद्यालय को आनंदघर बनाने का खुवाब कब और कैसे देखा आपने। एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को अपने भावों को दबाना न पड़े। जहाँ खुल कर कह सके वे सारी बातें जो करते होंगे वे शायद अपनी माँ से, अपने दोस्तों से या हर उस इंसान से जो उनके हृदय के बहुत समीप होगा। सोचती हूँ कि कितने नसीब वाले रहे होंगे वे बच्चे जो अपने घर की देहरी लॉंचते ही और अपनी माँ के आँचल की छाँव छोड़ते ही पा गए होंगे एक एक माँ, मूँछें वाली माँ। एक ऐसी मोछल्ली माँ जिससे उन्होंने पायी स्नेह और दुलार की बारिश और साथ ही शिक्षा की गुनगुनी धूप भी।

किताबें पढ़कर नहीं बल्कि आपने बच्चों को पढ़कर उन्हें पढ़ाना सीखा। अपने लिखा है कि कल्पना में पढ़ा देना आसान होता है पर वास्तविकता में यह लोहे के चने चबाने जैसा है। समझ पा रही हूँ मैं आपके भावों को और

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटेर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

काश! आप आज होते गिजुभाई

पास जादू की अद्भुत छड़ी थी या आपका व्यक्तित्व ही था इतना जादुई कि सामने वाला सम्मोहित हो जाए। शारीरिक साफ-सफाई, परिवेशीय स्वच्छता और अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय हों या व्याकरण जैसे क्लिष्ट विषय, आपने इतनी सहजता से पढ़ा दिए। एक बात बताऊँ आपको? वैसे मुझे आपकी यह बेरिंग विषय पढ़ाने के तरीके पढ़कर इसलिए भी खुशी हुई क्योंकि इन तरीकों में से काफी कुछ मैं हूबहू अपनाती हूँ। और ज़्यादा खुश होने की वजह भी यही थी कि मैं आपको पढ़कर जान पायी कि मैं सही दिशा में हूँ।

वो आपका डिक्शनर लिखाने का तरीका दिल और दिमाग दोनों को छू गया। मैं दूसरे दिन से ही अमल में लेने आ गई। वो आपकी सुबह से छुड़ी तक चलने वाली कहानी और उस कहानी के बीच में ही आपका बच्चों से सब कुछ कहा जाना। सिखा जाना उन्हें वो कठिन सी लगने वाली सीख जो रीत से पढ़ाते तो शायद कभी ना सिखा पाते। कभी-कभी ऐसी रीत से हटकर चलना भी अच्छा होता है जिस पर चलकर आपको मंजिल मिल जाए। आपका वो बच्चों के साथ खेलना और खेल-खेल में ही न जाने कितनी विषाएँ सिखा देना, किसी जादू से कम था क्या। अरे ! आपका वह वाक्या तो क्या कुछ सिखा गया जिसमें आपने बच्चों के माता-पिता को भी सिखाने के क्रम का प्रथम पायदान देा। आपका वो कहानी कहने का तरीका और उस कहानी में ही बच्चों को सब कुछ सिखा देना। ‘एक था राजा और उसके थी सात रनियाँ, सातों के सात राजकुमार और सातों के सात राजकुमारियाँ, उन सातों राजकुमारियों के सात-सात महल और महल में सात-सात मोती के पेड़.....’ अहा ! बच्चे क्या, शांति में उसुकता जगप दे ये तरीका। बातें का खेल, बच्चों की अभिमुखता, कहानी की रोचकता और अव्यवस्था व शोर के प्रति बच्चों की नाराजगी.....।एक तीर से कितने ही निशाने साध लिए आपने। अब तो बच्चों को छुड़ी-चुड़ी भी नहीं चाहिए। क्या सच में आपके

व्यंग्य

पूरन सरमा

लेखक व्यंग्यकार है



यह वाक्या पुलिस विभाग का है। वैसे भारतीय पुलिस पर लिखना आउट ऑफ़टेड माना जाने लगा है, क्योंकि पुलिस का चेहरा दिनों दिन मैला ही होता जा रहा है। पुलिस की किसी से भी बात करो, मुंह बनाकर कहता है- ‘छोड़े यार, ये तो होते ही ऐसे हैं। बचकर बहो वरना कोई झूठा मामला बनाकर फंसा दोगे,’ अब बताइये कि पुलिस के बचाव में कोई क्या कह या कर सकता है। पुलिस वाला यदि वदी में है तो मामला सातवें आसमान पर होता है। छोटा सा कान्स्टेबल भी किसी को भी धमकाने की पोजीशन में आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या पुलिस विभाग में पैदा हुई है- वह है रिश्ततखोरी। बिना दक्षिणा के हाथ ही नहीं धरने देते। खासितय यह भी रिश्तत आपसे ही नहीं, दूसरे से भी ले लेंगे और करने के नाम पर होती है सिर्फ लीपा-पोती। इसलिए लोग आजकल पुलिस में जाने से कतरने लगे हैं और मामले अपने स्तर पर ही सल्टाने में लग जाते हैं। यह है हमारी पुलिस की पूर्व भूमिका, अब मुझे उस वाक्या पर आना चाहिए, जिसका जिक्र

आवश्यक है, यह आपने उस समय समझाया जब इसे समय की बर्बादी से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था। सिर्फ बच्चों को सिखाने तक ही नहीं अपने साथी शिक्षकों की सोच बदलने और अधिकारियों के शिक्षा के प्रति नजरिये के बदलाव के लिए भी अपने सार्थक प्रयास किए। अगर अपने बच्चों में अमरीी हो तो कौन सा खजाना नहीं मिल सकता। जीवन जीने की कला सिखा देना भी इतिहास, भूगोल, व्याकरण और गणित जैसे विषयों से कम कठिन नहीं जिसमें आपने उन्हें पारंगत कर दिया।

आपको पढ़ने के बाद तो मैंने भी बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है चली आ रही रीत से अलग हटकर चलना। वैसे कुछ ऐसा ही करती आई हूँ मैं। अब तक आपको पढ़कर बहुत कुछ सीखा मैंने और सबसे ज्यादा पाया है संतोष कि सही रास्ते पर हूँ मैं क्योंकि बहुत कुछ वैसे ही कर रही हूँ जैसे आपने सुझाया। बहुत कुछ है कहने को आपसे जो शायद मैं मिलती तो बता पाती कभी। दिखा पाती आपको कि कैसे आपके प्रयोग के 100 साल बाद भी वे इतने प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो या नई शिक्षा नीति 2020, सबमें आपके शैक्षिक प्रयोगों एवं विद्यालयों के परिवेश को आनंदमय बनाने की पैरवी का प्रभाव दृश्य है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी मंशा आज हर रचनात्मक व जुझारू शिक्षक के मन में है। आपने जो सपना आज से एक सदी पहले देखा था वह दिवास्वन आज शिक्षा का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक आनंदमय विद्यालयीय परिवेश के स्वप्न को साकार करने का भरसक प्रयास करूँगी। एक ऐसा परिवेश जहाँ बच्चे निर्भय होकर अपने ज्ञान की सर्जना कर सके। जहाँ बच्चे सदृश्य, संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनकर एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने भारत का सुनहरा भविष्य गढ़ सकें। आनंदमय विद्यालय की राह पर एक शिक्षिका।

पुलिस से बचाओ

मैंने प्रारम्भ में किया है। मेरी आपबीती है। स्कूटर से जा रहा था अजमेरी गेट। रास्ते में रेड लाइट हुई तो रुकना ही था। परन्तु मैंने ब्रेक मारा तो स्कूटर कुछ, स्टॉप लाइन से आगे आ गया, मैं उसे पीछे लेता, उससे पहले ही भारतीय पुलिस आ गई और बोली- ‘आजाओ, स्कूटर एक तरफ लगाओ और चलती के लिए ज़ुर्माना भरो।’ मैंने स्कूटर को साइड में लगाया और बोला- ‘क्यों क्या बात हो गई सर ?’ पुलिसवाला बोला- ‘पहले स्कूटर चलाना सीखो और यातायात के नियमों की जानकारी भी लो अन्यथा आपके लिए पैदल चलना ही उचित रहेगा।’ मैंने फिर वही बात दोहराई- ‘आखिर हुआ क्या है ?’ ‘हुआ यह है कि आपने यातायात नियमों की अवहेलना की है, इसलिए दो सौ रुपये की रसीद कटवाओ।’ पुलिसवाले ने यह कहा तब तक उसका दूसरा साथी भी एक पुस्तिका लेकर मुझे घूरने लगा और बोला- ‘जल्दी निकालो रुपये, हमारे पास टाइम नहीं है। बहस करनी है तो कंट्रोल रूम में आ जाना।’ मैं बोला- ‘दो सौ रुपये तो मेरे पास इस समय नहीं हैं।’ एक पुलिसवाला बोला- ‘कोई बात नहीं, पैसा जमा करवाकर स्कूटर कंट्रोलरूम आँपिस दे ले लेना।’ इस बार मैं रिरियाया- ‘देखो मामला यहीं रफा-दफा कर लीजिये। मुझे बहुत जरूरी काम से

अस्पताल तक पहुंचना है।’ पुलिसवाले भांप गये थे कि मेरी जेबें खाली हैं अतः वे ईमानदार और ड्यूटी के वफ़दार हो गये थे, बोले- ‘जाओ अपना काम करो, माथा खाने की आवश्यकता नहीं है।’ मैंने आखिर पैंतरा मारा- ‘देखिये मैं एक हिन्दी साहित्यकार हूँ, अखबारों में लिखता रहता हूँ- आपको जो भी करना है अभी करके मामले को रफा-दफा करिये।’ ‘अच्छा आप साहित्यकार हैं। इतने पढ़े-लिखे होकर भी नियमों की अवहेलना करते हैं। अभी कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता ? माफ़करिये आपको स्कूटर तो कंट्रोलरूम से ही लेना होगा।’ मैंने पचास रुपये की पेशकश की तो वे लोग और भड़क उठे- ‘शर्म नहीं आती आपको। साहित्यकार होकर रिश्तत देना चाहते हैं। पुलिस को बदनाम करते हैं। दो सौ की रसीद कटवानी है तो जल्दी करो वरना अपना रास्ता नापो।’ वे पचास के नोट से दुखी थे और दो सौ की धोस देकर मुझे एक सौ पर लाना चाहते थे। लेकिन मैं ठहरा साहित्यकार पचास से ज्यादा जेब में कभी रूपया लेकर ही नहीं पाया था। आखिर हाथकर मैं उससे माथापच्ची करके घर लौट आया। पत्नी को घटनाक्रम से अवगत कराया तो वह भी गुस्से से भर गई और बोली- ‘आप पैदल ही चला करो, स्कूटर चलाना आपकी बस की नहीं है। पुलिस का चक्र बुरा

परिचालन ठेकेदारों को देंगी और तब भारत सरकार कहेगी कि हमने कोई निजीकरण नहीं किया है। यह तो राज्य सरकारों ने किया है। केंद्र सरकार निजीकरण के आरोपों से भी बच जाएगी और निजीकरण का वांछित लक्ष्य भी हासिल कर लेगी। यह मोदी जी की शैली है की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन, निर्माण के नाम पर निजी खिलाड़ियों (कॉर्पोरेट घरानों) को सौंपे जा चुके हैं और अब वहां स्थिति यह है कि वेटिंग रूम में रुकने का भी शुल्क यात्रियों से लिया जा रहा है। रियायतिंग रूम की दरें 3 घंटे और 6 घंटे के आधार पर तय की गई हैं। रेल मंत्री जी से पूछना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है जो स्टेशन के प्लेटफ़र्म पर पड़ा रहना चाहता है। प्लेटफ़र्म में रुकते हैं, ठहरते हैं, जो विलंबित रेल गाड़ियों का ईंतजार कर रहे होते है। इन विलंबित रेलगाड़ियों के विलंब के लिए रेलवे जिम्मेदार है ना कि ईंतजार कर रहे-यात्री।

प्रधानमंत्री जी की पसंद के नाम पर यात्रियों को और उनकी गाड़ियों को अनावश्यक ढंग से लेट किया जाता है। अभी एक दिन मैं स्वयं रेल से भोपाल जा रहा था। गाड़ी (ट्रेन) बिल्कुल निर्शांति समय पर चल रही थी परंतु उसे भोपाल रेलवे स्टेशन से आधा पत्नीग पहले यानी निशातपुरा और भोपाल के बीच खड़ा कर दिया गया। वहां यह ट्रेन लगभग 35 से 40 मिनट तक खड़ी रही। उसके बाद वहां से वंदे भारत गुजरी जो भोपाल के ही दूसरे स्टेशन रानी कमलापति तक जाती है। मुश्किल से तीन-चार मिमट में मेरी ट्रेन भोपाल पहुंच जाती और 5-7 मिनट में वह आगे चली जाती। परंतु, प्रधानमंत्री जी के स्वप्न की गाड़ी वंदे भारत को निकालने के लिए दूसरी समय से चल रही गाड़ी को करीब 40 मिनट खड़ा करके रखा गया। कटौल रूम जो गाड़ियों के निकलने की अनुमति देता है, उसके अधिकारियों को पता है कि प्रधानमंत्री जी की पसंदीदा गाड़ी वंदे भारत है और इसीलिए दूसरी गाड़ियां कितनी ही लेट क्यों ना हो जाएं, वंदे भारत को समय पर पहुंचना चाहिए। उच्च अधिकारियों की यह चाटुकारिता निंदनीय है। जैसे पहले राजा-महाराजाओं की सत्ता थी जो भोपाल को रोक कर पहले निकला जाता था। आजकल नये राजा-महाराजाओं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों को निकालने के लिए सारी सड़कें बंद कर दी जाती हैं। और लगभग ऐसा ही आजकल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भारतीय रेलवे में भी, हो रहा है। भले ही भारत सरकार ने घोषणा न की हो परंतु सरकार का हर कदम रेलवे के निजीकरण की ओर ले जा रहा है। देश की जनता को और रेल मजदूरों के संगठनों के नेताओं को इन संभावित खतरों को समझना चाहिए।

भूलने लायक नहीं है भोपाल गैस कांड

त्रासदी के 40 बरस

स्वराज करुण

संसार का समय-चक्र निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे भयानक हादसे होते हैं, जिन्हें वह समय –चक्र के चक्कर में फँस कर भूल जाता है। लेकिन कई हादसे भूलने लायक नहीं होते। भोपाल के लोग तो नहीं भूले होंगे लेकिन दुनियादारी में व्यस्त बाहर के लोगों ने शायद भोपाल गैस कांड जैसे भयंकर हादसे को लगभग भुला दिया है जिसमें असमय ही मौत का शिकार हुए हजारों लोगों की आज 38 वीं बरसि है।



काबाईड फैक्ट्री में हुए घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट (मिक) के घातक रिसाव से ये लोग वरुण काल के मुँह में समा गए थे। इन संधी दिवांतों को विनम्र श्रद्धांजलि। वह के हजारों लोग आज भी उस जहरीली गैस के दुष्प्रभाव से किसी न किसी जटिल बीमारी से पीड़ित हैं।

इस भयानक हादसे ने भोपाल के पर्यावरण को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। हवा विषैली हो गयी थी। पानी जहरीला हो गया था। अधिकांश लोग विषाक्त हवा में दम घुटने की वजह से मारे गए और भयभीत भीड़ की भागदड़ में कुचलकर भी बड़ी संख्या में मौतें हुईं। ऐसे विषाक्त माहौल में

समय -समय पर हुईं व्यर्थ की लड़ाइयों में हो चुकी है । हो भी रही है। अफगानिस्तान पर वर्ष 2001 में और इराक पर वर्ष 2003 में वरूरता के साथ हुए अमेरिकी आक्रमण और इन दिनों यूक्रेन पर बेहदमी के साथ हो रहे रूसी हमले इसके ताज़ा उदाहरण हैं। इसके दशकों पहले हुए प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध और वियतनाम पर अमेरिकी हमलों से लाखों-करोड़ों मौतों को भी हमें याद रखना चाहिए। चाहे औद्योगिक हादसे हों या जन-संसार के बेहदमी और बेशर्मा भरे युद्ध, इन सबको रोका जाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण ,मैत्रीपूर्ण और खुशहाल विश्व का निर्माण होना चाहिए।

है, जाओ ये लो दो सौ और स्कूटर लेकर आओ वरना स्कूटर ग्राम क अस्थिपंजर का रूप को ग्रहण कर लेगा।’

मैं भागा कंट्रोलरूम, जानकारी की तो उन्होंने दो सौ की रसीद काटी और बताया कि स्कूटर तो ब्रह्मपुत्री थाने से ले लें, क्योंकि आपका थाना वहीं है। मैं फिर रिक्शा करके ब्रह्मपुर्ी थाने पहुंचा तो वहाँ पुलिस वाले अपनी मूँछें पर बल लगा रहे थे। मैंने दो सौ रुपये की रसीद बताई स्कूटर देने को कहा। इस बार पुलिस मूँछें से रसीी और बोली- ‘यह स्कूटर तो अशोक नगर थाने में है। आप यह रसीद दिखाकर वहीं से स्कूटर ले लो।’ मैं फिर वहीं से अशोक नगर थाने पहुंचा। मैंने वहाँ रसीद बताई तो होशियार सिंह कान्स्टेबल बोला- ‘यह स्कूटर यहीं है, परन्तु चाय-पानी तो कराओ।’ मैंने कहा- ‘जब ज़ुर्माना भर दिया तो अब चाय-पानी का क्या सवाल है ?’ होशियार सिंह बोला- ‘तो पिर कल आना, अभी टाइम नहीं है।’ यह कहकर वह कुर्सी पर पसर गया। मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया एक पल को। अब तक मैं आने-जाने के किराये रूम में साठ रुपये खर्च कर चुका था। मन ने कहा- ‘वहाँ सौ रुपये देकर मामला सलता लेता तो ठीक रहता।’ मैंने कहा होशियार सिंह से- ‘चाय-पानी का मतलब ?’ वह बोला निःसंकोच भाव से- ‘पचास रुपये।’ झूख मारकर पचास रुपये देकर स्कूटर स्टार्ट किया और घर आकर लोटे गया परन्तु मन आत्मलालिप्त से भरा हुआ था। भारतीय पुलिस का यह चेहरा कब बदलेगा- मैं नहीं जानता।’ शिकायत करूँ तो किस्से करूँ, यह भी नहीं जानता। परन्तु मैं भारतीय पुलिस को जान गया था।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल ने मदरसों को चलाने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने, उनमें योग्यता में सुधार करने और मदरसों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अध्ययन की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से मदरसा अधिनियम लागू किया था। मदरसा अधिनियम की धारा 9 बोर्ड के कार्यों से संबंधित है जो व्यापक हैं और अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम सामग्री निर्धारित करने, डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने, परीक्षाओं का संचालन करने, परीक्षा आयोजित करने के लिए संस्थानों को मान्यता देने, अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करने और अन्य आनुवंशिक कार्यों से संबंधित है। इन कार्यों का प्रयोग शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। मामला सबसे पहले तब सामने आया जब एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ताओं में से एक को अशकालिक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस याचिका में प्रार्थना की गई थी कि कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और उसकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो मुख्य प्रश्न उठा वह यह था, कि क्या मदरसा अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के विनियमन के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के विचारों और हितों के अनुसार संस्थान के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है। हालांकि, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार का तात्पर्य छात्रों को शिक्षा का मानक प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों का दायित्व और कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मदरसा अधिनियम बोर्ड को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करने, परीक्षाओं का संचालन करने, शिक्षकों की योग्यता और मदरसों में शिक्षा के मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और भवनों के

मदरसा अधिनियम-2

शिक्षा का मानक प्रदान करना मदरसों का दायित्व

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम बोर्ड को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करने, परीक्षाओं का संचालन करने, शिक्षकों की योग्यता और मदरसों में शिक्षा के मानकों के रखरखाव

को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और भवनों के मानकों की अनुमति देता है। मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित है, क्योंकि वे मान्यता के उद्देश्य को पूरा करते हैं।

मानकों की अनुमति देता है। मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित हैं। क्योंकि, वे मान्यता के उद्देश्य को पूरा करते हैं, यानी मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता में सुधार करना और उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाना। यह कानून मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और रोज़गार पाने में भी सक्षम बनाता है। न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है, कि यदि कोई कानून मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त किया जाना अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून के अमान्य होने का पता संविधान के प्रावधानों को व्यक्त करने के लिए लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तथ्य कि राज्य विधानमंडल ने मदरसा शिक्षा को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21-ए और 30 की परस्पर क्रिया के बारे में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21-ए राज्य पर प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व अधिरोपित करता है। इसके परिणामस्वरूप आरटीई अधिनियम लागू किया गया। अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है। संवैधानिक योजना राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने और अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करने के दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की अनुमति देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि 2004 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई शिक्षा अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन करती है। क्योंकि, एक तो आरटीई अधिनियम, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत मौलिक अधिकारों की पूर्ति की सुविधा प्रदान करता है, में एक

प्रविष्टि प्रावधान है जिसके द्वारा यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए एक धार्मिक अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 30 द्वारा संरक्षित



है। तीसरा, बोर्ड और राज्य सरकार के पास मदरसों के लिए प्षिका के मानकों को निर्धारित करने और विनियमित करने के लिए पर्याप्त नियामक शक्तियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे मदरसा अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पृथकता के सवाल को पर्याप्त रूप से हल करने में विफल रहने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया और अंत में उचित निष्कर्ष नहीं दिया। पूरे कानून को हट बार रह करने की आवश्यकता नहीं है जब कानून के कुछ प्रावधान संवैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। कानून केवल इस हद तक अमान्य है कि

यह संविधान का उल्लंघन करता है। उच्च शिक्षा के विनियमन से संबंधित मदरसा अधिनियम के प्रावधानों को शेष अधिनियम से अलग किया जा सकता है। इन विशिष्ट प्रावधानों को अलग करने के बाद भी, अधिनियम को वास्तविक और ठोस तरीके से लागू



किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि पूरे कानून को हट बार रह करने की आवश्यकता नहीं है, जब कानून के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक रूप से लागू नहीं माना जाता है। यह कानून केवल इस हद तक अमान्य है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। मदरसा शिक्षा अधिनियम को केवल इस हद तक असंवैधानिक घोषित किया गया था कि यह यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव में होने के कारण फाजिल और कामिल डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है। इसमें कहा गया है कि एकमात्र कमजोरी उन प्रावधानों में निहित है जो उच्च

शिक्षा से संबंधित हैं, अर्थात् फाजिल और कामिल और इन प्रावधानों को मदरसा अधिनियम के बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को कानून के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है, तो मदरसा अधिनियम को वास्तविक और पर्याप्त तरीके से लागू किया जा सकता है।

इस प्रकार, केवल फाजिल और कामिल (डिग्री) से संबंधित प्रावधान असंवैधानिक हैं, और मदरसा अधिनियम अन्यथा वैध रहता है। इससे अलावा, इसने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए। बोर्ड, राज्य सरकार की मंजूरी से, यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना आवश्यक मानक की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें। मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है और सूची तीन की प्रविष्टि 25 में इसका पता लगाया जा सकता है। इससे पहले अप्रैल में, विवादित फैसले पर रोक लगाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला और उसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया सही नहीं था। मदरसा अधिनियम, 2004 के अधिकारों को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने 22 मार्च के आदेश में कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन माना था। इसने उत्तर में प्रदेश सरकार से ऐसे संस्थानों के छात्रों को नियमित स्कूलों में समायोजित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। यह भी कहा गया था कि यदि आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के बिना न रहें।

व्यक्ति

सीमा जयंत भिसे

(समाजसेवी और लेखिका)



कोई कितना ईमानदार हो सकता है, इसका कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन, यदि कोई अपने हालात को देखते और समझते हुए भी अपनी ईमानदारी की सीमा लांघ ले, तो वह एक उल्लंघन करने वाली घटना तो होगी। यह बात उस समय की है, जब सीसीटीवी कैमरे का दौर नहीं था। सुनीता का ट्रांसफर बैंक की एक शाखा में हुआ था। दीपावली पास ही थी। उस साल बरसात भी जरा ज्यादा समय तक चली। नए स्तर पर ट्रांसफर होने के बाद सुनीता का पहला दिन था। बैंक की शाखा के आसपास गाड़ी पार्किंग को लेकर समस्या आ रही थी। 8-10 दिन में सभी से थोड़ा परिचय होने के बाद काम का रूटीन बनने लगा। मुझे याद है, उन दिनों में बैंक में कार लोन और अन्य ट्रांजेक्शन अधिक था। लॉकर के लिए भी कस्टमर की लाइन लगी थी। पहले सुनीता ने काम पूरा किया। उसके बाद ही भीड़ लगी थी। ट्रांजेक्शन टाइम समाप्त हुआ। अब बैंक बंद होने के पूर्व चपरासी के अपने काम शुरू हुए। लॉकर

ईमानदारी अनमोल है उसे कोई कैसे खरीदे ?

बैंक बंद होने के पूर्व चपरासी के काम शुरू हुए। सुनीता ने खोलकर देखा तो काफी कीमती गहने थे। आदर और बढ़ गया। बाद में उस चपरासी ने थैली की मालिक महिला से कोई इनाम लेने से भी इंकार करके अपनी ईमानदारी को प्रमाणित कर दिया।

रूम बंद करने के पूर्व चेकिंग के लिए सुनीता जाने ही वाली थी, उतने में चपरासी प्रभाकर म्हस्के ने एक बड़ी सी थैली सुनीता के टेबल पर रखी। कहा कि यह लॉकर रूम में मिली है। सुनीता ने खोलकर देखा तो काफी कीमती गहने थे। सुनीता ने सबसे पहले म्हस्के जी की तरफ देखा और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर लॉकर रजिस्टर से आज की एंट्री चेक करना शुरू की। चेक करते समय सुनीता के मन में म्हस्के के प्रति आदर और बढ़ गया। कई विचार आने लगे, क्या यह थैली म्हस्के को मिलने के बाद उनके मन में क्या आया होगा? उसके स्तर

के व्यक्ति को जहां घर में अभाव है, पत्नी रोज निकलते समय सामान की लिस्ट पकड़ाती होगी। इतने अभाव के बावजूद उन्होंने थैली सुपुर्द कर दी। यह बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इससे बहुत बड़ी थी। लॉकर एंट्री वाले सभी लोगों को फोन किए गए। ये फोन दीपावली की शुभकामनाओं के बहाने किए गए। सभी ने शाखा की बदले में शुभकामना दी और बैंक की तारीफ भी की। केवल एक महिला कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। बाद में उसका फोन आया। घर के किसी

कार्यक्रम में बहुत व्यस्त होने से वे ज्यादा बोल नहीं पाईं। उसने सुनीता को रात को फोन करूंगी कहा। गहनों की वह थैली बैंक की कस्टडी में रखकर सुनीता ने मुख्यालय को सूचित किया। इसके बाद बैंक का शटर बंद हुआ। उस महिला का रात को भी फोन नहीं आया। सुबह उसका फोन आया। सुनीता ने उससे बात की फिर भी उसे महिला को कुछ याद में नहीं आ रहा था। सुनीता ने उससे पूछा आपके यहां कार्यक्रम कब है? उसने कहा आज शाम को है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। अगले दिन सुनीता रोज के अनुसार बैंक पहुंची। दोपहर में वह महिला रोते हुए, बैंक में आई और उसने कहा जब मैं कार्यक्रम की तैयारी करने लगी, तब मुझे ध्यान में आया कि मेरे गहनों की थैली कल यहीं रह गई। इसमें हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के जेवररात हैं। जो आने वाली बहू को पहनाए

जाते हैं। उसने सभी गहनों की डिजाइन, नम बराबर बताएं। सभी जानकारी सही थी। तब सुनीता ने म्हस्के की को बुलाकर उनके सामने सारी बात बताई। उस महिला को उनकी इस ईमानदारी पर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत पर्स से 10 हजार रुपए निकालकर म्हस्के को दिए। यह भी कहा कि आप जितने कहेंगे, मैं उतने देने के लिए तैयार हूं। पर म्हस्के जी ने वह रकम भी लेने से इनकार कर दिया। बाद में शाखा के कर्मचारियों ने मिलकर म्हस्के जी का सम्मान किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कुछ छोटे और खुशियां बहुत बड़ी होती है। जिसमें समाधान अधिक होता है। ईमानदारी पर हुए सम्मान पर म्हस्के जी को जो खुशी हुई वह गहनों की उस थैली की कीमत से बहुत ज्यादा थी। यह खुशी खरीदी नहीं जा सकती है।

धर्म संस्कृति

डॉ. सौरभ मालवीय

लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

महाकुंभ मेला भारत की गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर है। यह मेला हमारी गौरवमयी संस्कृति का संचाहक है। यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति एवं आस्था को दर्शाता है। यह कला-संस्कृति, गायन, नृत्य, हस्तकला को प्रोत्साहित करता है। इस मेले में संपूर्ण भारत की झलक मिलती है। इसमें प्राचीन भारत के साथ-साथ आधुनिक भारत का भी बोध होता है। मेले में सम्मिलित होने से आत्मा के अजर अमर होने की भारतीय मान्यता पर विश्वास अत्यधिक दृढ़ हो जाता है। यह मेला भारतीय दर्शन का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ कुंभ मेले का शुभारंभ होगा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ इसका समापन होगा। शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर तथा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा।

सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व प्रयागराज हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां गंगा, यमुना एवं सरस्वती का अद्भुत संगम होता है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति बारहवें वर्ष तथा प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के मध्य छह वर्ष के अंतराल पर अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा एवं मेले का अर्थ एक स्थान पर एकत्रित होना है। कुंभ मेला अमृत उत्सव के नाम से भी प्रसिद्ध है। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। उस समय सूर्य एवं चंद्रमा, वृश्चिक राशि में तथा वृहस्पति, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिवस को अति शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से

भारतीय संस्कृति का प्रतीक है महाकुंभ मेला

खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। उस समय सूर्य एवं चंद्रमा, वृश्चिक राशि में तथा वृहस्पति, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिवस को अति शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से मनुष्यों के बारह वर्ष के समान होते हैं। इसलिए कुंभ भी बारह होते हैं। इनमें से चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं तथा शेष आठ कुंभ देवलोक में होते हैं। देव एवं दानवों के इस संघर्ष के दौरान भूमि पर अमृत की चार बूंदें गिर गईं। ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में गिरीं। जहां-जहां अमृत की बूंदें गिरीं वहां पर तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया। तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है जहां मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जहां अमृत की बूंदें गिरीं, उन स्थानों पर तीन-तीन वर्ष के अंतराल पर बारी-बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन तीर्थों में प्रयाग को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। इन नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत में महाकुंभ धार्मिक स्तर पर अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों-करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के सम्मिलित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लगभग डेढ़ मास तक संचालित होने वाले इस आयोजन में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की जाती है। उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी नगरी अलग से बसा दी गई है। यहां तीर्थयात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यह आयोजन प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों एवं पुलिस की सहायता से आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर-दूर से साधु-संत आते हैं। कुंभ योग की गणना कर स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान से पूर्व मुहूर्त न नागा साधु स्नान करते हैं। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटी रहती है। उनके बाल लंबे होते हैं तथा वे चस्कों के स्थान पर शरीर पर मृगचर्म धारण करते हैं। स्नान के लिए

विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े भव्य रूप से शोभा यात्रा की भांति संगम तट पर पहुंचते हैं। ये साधु मेले का आकर्षण का केंद्र होते हैं। उत्तर प्रदेश धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। महाकुंभ मेले के कारण एवं विश्भर से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ पर्यटक भी आएंगे। इसलिए प्रयागराज के ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग, स्मार्ट सिटी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। मेला प्रशासन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था एवं सुविधा को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे उन्हें स्मरणीय अनुभव प्राप्त हो सके तथा वे यहां से प्रसन्नतापूर्वक वापस जाएं। पर्यटन विभाग जिन कॉरिडोर एवं नवीनीकरण परियोजनाओं की देखरेख कर रहा है, उनमें से मुख्य रूप से भारद्वाज कॉरिडोर, मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, द्वादश माधव मंदिर, पड़िला महादेव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर आदि सम्मिलित हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अक्षयवर्द्ध कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर एवं पातालपुरी कॉरिडोर सम्मिलित हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण नागवासुकी मंदिर का नवीनीकरण कार्य एवं हनुमान मंदिर कॉरिडोर का कार्य करवा रहा है।

पौधारोपण

महाकुंभ मेले के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश को हरभरा बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए संपूर्ण राज्य में 2.71 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग, नगर निगम एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण मिलकर कार्य कर रहे हैं तथा संयुक्त रूप से राज्यभर में अभियान चला रहे हैं। वन विभाग द्वारा 29 करोड़ रुपये की लागत से 1.49 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग संपूर्ण जिले में सड़कों के किनारे पौधे लगाएगा। नगर में आने वाली मुख्य सड़कों पर सघन पौधारोपण किया

कुंभ देवलोक में होते हैं। देव एवं दानवों के इस संघर्ष के दौरान भूमि पर अमृत की चार बूंदें गिर गईं। ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में गिरीं। जहां-जहां अमृत की बूंदें गिरीं वहां पर तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया। तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है जहां मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जहां अमृत की बूंदें गिरीं, उन स्थानों पर तीन-तीन वर्ष के अंतराल पर बारी-बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन तीर्थों में प्रयाग को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। इन नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

जा रहा है। सड़कों के किनारे नीम, पीपल, कदंब एवं अमलतास आदि के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत सरस्वती हाईटेक सिटी में 20 हेक्टेयर में 87 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वन विभाग नगर के कुछ क्षेत्रों में पौधे लगाएगा। नगर में हरित पट्टी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्राकृतिक उत्पादों को प्रोत्साहन भारतीय जीवन शैली सदैव से प्रकृति के लिए सुखद रही है। देश के अनेक राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्तों पर भोजन परोसा जाता है। धार्मिक आयोजनों में होने वाले सामूहिक भोज में भी पत्तलों पर भोजन परोसा जाता है। महाकुंभ मेले में प्राकृतिक उत्पाद जैसे दाना, पत्तल, कुल्हड़ एवं जूट व कपड़े के थैलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें पॉलीथिन एवं सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पॉलीथिन एवं प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

स्वच्छता पर बल हमारे देश में आत्मा की शुद्धि के साथ-साथ शारिरिक स्वच्छता पर भी विशेष बल दिया जाता है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने के दृष्टिगत क्षेत्र में लगभग डेढ़ लाख शौचालय एवं मूत्रालय स्थापित किए जा रहे हैं। इनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। इसमें तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी की निगरानी का दायित्व गंगा सेवा दूतों को सौंपा गया है। वे प्रातः एवं सायं इनकी जांच करेंगे। क्यूआर कोड से स्वच्छता की मॉनीटरिंग की जा रही है। यह ऐप बेसड फ्रीडबैक देगा, जिसके माध्यम से शीघ्र से शीघ्र सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बार मैनुअल शौचालय स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु

जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम से कुछ क्षणों में पूरी तरह उन्हें स्वच्छ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेसपूल ऑपरेशन प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मेला क्षेत्र में स्थापित शौचालयों के सेप्टिक टैंक को रिक्त किया जाएगा। सेप्टिक टैंक रिक्त करके यहां से वेस्ट को एसटीपी प्लांट या अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

यातायात सुविधा प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए यातावात की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज आने वाली बसों, रेलगाड़ियों एवं वायुयान की संख्या में वृद्धि की जा रही है। महाकुंभ के लिए रेलवे द्वारा लगभग 1200 रेलगाड़ियां तथा परिवहन विभाग द्वारा सात हजार बसों का संचालन किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए योगी सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने पर सात टोल प्लाजा को टैक्सेस फ्री करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक चित्रकूट मार्ग पर अम्पुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग पर ग्रेने टोल प्लाजा, मिर्जापुर मार्ग पर मुंगारी जाएगा। यह सुविधा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगी। यद्यपि यह सुविधा माल वहक व्यवसायिक वाहनों को नहीं मिलेगी। इस समयवधि में सरिया, सीमेंट, बालू एवं इलेक्ट्रीनिक्स सामान से भरे वाहनों से टोल लिया जाएगा। किंतु व्यवसायिक पंजीकृत वाहन एवं कार आदि से भी टोल नहीं लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार का कुंभ मेला स्वयं में विशेष होगा।

भोपाल के 37 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत

भोपाल (नप्र)। भोपाल में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रविवार 1 दिसंबर से भोपाल के सभी नगरीय 37 थानों में सायबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की की गई। पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने हबीबगंज थाने रविवार को इसका इनोग्रेशन किया। हबीबगंज थाने के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टीकल्चर की शिकायत पर नई व्यवस्था के तहत पहली शिकायत दर्ज की गई है। हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी करीब 400 पुलिस कर्मचारी संभालेंगे। इसके पहले इन सभी पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता और तकनीकी नॉलेज बढ़ाने को लेकर सभी थानों के अधिकारियों और कर्मचारी को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। जानकारी के अनुसार सायबर अपराध लगतार बढ़ रहे हैं। अब तक में आमजन को साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए सायबर शाखा जाकर आवेदन देना पड़ता था। शहर में एक ही साइबर थाना होने और अधिकतर थानों से काफी दूरी के कारण पीड़ितों को शिकायत के लिए सायबर थाने जाने में काफी समय लगता था और काफी परेशानी होती थी।

5 लाख तक की शिकायत दर्ज कर सकेंगे

राजधानी भोपाल में कुछ वर्षों में सायबर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होने से

रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टीकल्चर की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज



शाखा में शिकायतें पेंडिंग हो रही हैं। इन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आमजन की सहूलियत के लिए 1 दिसंबर से पीड़ित 5 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी, ठगी की शिकायत संबंधित थानों में कर सकेंगे। जल्द शिकायत होने से पीड़ित का पैसा साइबर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर होल्ड करेगी, जिससे रिफंड होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

प्रशिक्षण में शामिल हुए चार सौ कर्मचारी पुलिस अधिकारियों और

कर्मचारियों की कार्यकुशलता, तकनीकी नॉलेज बढ़ाने के लिए नगरीय पुलिस भोपाल के 37 थानों के निरीक्षक से आरक्षक स्तर के लगभग 400 अधिकारी और कर्मचारियों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें एनसीसीआरपी, जेएमआईएस एवं सीईआईआर पोर्टल तथा सायबर क्राइम की रोकथाम, टेक्निकल एनालिसिस, पब्लिक अवेयरनेस, इन्वेस्टिगेशन इत्यादि से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया

गया है।पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने हबीबगंज थाने रविवार को इसका इनोग्रेशन किया।

400 पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में बताया गया कि सायबर क्राइम की शिकायत को किस प्रकार से पोर्टल पर अपलोड करना, फेंसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, इत्यादि से

जानकारी मंगाना एवं बैंक से अकाउंट डिटेल, सीडीआर निकालना, साक्ष्यों एवं जानकारी को एकत्रित करने के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया है। चैन सिस्टम से करना होगा काम प्रशिक्षण के दौरान पुलिस उपायुक्त क्राइम अखिल पटेल ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि सायबर क्राइम में अपराध की जड़ तक जाने के लिए चैन सिस्टम से कार्य करना होगा।

डिजिटल साक्ष्य-दस्तावेज कैसे जुटाएं, बताया

इसके लिए तकनीकी ज्ञान और संसाधन होना बेहद जरूरी है। सायबर अपराधों से निपटने एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए सभी कर्मचारियों को टेक्नीकल रूप से निपुण होना पड़ेगा। पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल ने सायबर क्राइम अनुसंधान में आने वाली तकनीकी दिक्र्तों, दीगर प्रदेशों से समन्वय तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित किए जाने वाले डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज इत्यादि के सम्बंध में सारगर्भित मार्गदर्शन दिया है।

किसने दर्ज कराई पहली एफआईआर

65 वर्षीय जय गोविंद लाला लाजपतराय सोसाइटी हबीबगंज थाना क्षेत्र में रहते हैं। वह असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टीकल्चर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्नेपडील से 250 रुपए कीमत का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। तय समय में डिलीवरी नहीं होने पर गूगल से स्नेपडील कस्टमर केयर का नंबर सर्व किया। शिकायत दर्ज कराने यहां कॉल किया, तब साइबर जालसाज ने स्नेपडील कॉल सेंटर कर्मचारी बताया। उसने कहा कि आपने जो ऑर्डर दिया था, उसका अमाउंट ऑन लाइन जमा करना था।

छात्रा से बेड टच करने पर गेस्ट टीचर गिरफ्तार

परिजन ने स्कूल घेरा, शिकायत पर कार्रवाई; जनजातीय विभाग ने नौकरी से निकाला



धनराम लौवंशी, आरोपी

खंडवा (नप्र)। आदिवासी बाहुल्य खालवा क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रा के साथ बेड टच का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला स्कूल का टीचर था, जो बतौर गेस्ट फैकल्टी में नौकरी कर रहा था। छात्रा के साथ इस तरह के कृत्य को लेकर परिजनों ने स्कूल को घेर लिया। जनजातीय कार्य विभाग ने तत्काल निर्णय लेकर गेस्ट टीचर को नौकरी से निकाल दिया। इधर, शनिवार को मिली शिकायत पर खालवा पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो समेत एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। मामला शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम उदियापुर माल की है। जो कि खालवा से 15 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी धनराम पिता आशाराम लौवंशी निवासी ग्राम खालवा है।छात्रा की शिकायत के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

पढ़ाई की बात को लेकर किया बेड टच: 11 वर्षीय छात्रा ने बताया कि आरोपी धनराम ने शुक्रवार के दिन पढ़ाई की बात को लेकर बेड टच किया। कमर और सीने में चिमटी ली। टीचर की करतूत उसने घर जाकर माता-पिता को बताई।

परिजनों ने थाने आकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की। आरोपी धनराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अफसर बोले- टीचर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया: जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त विवेक पांडेय का कहना है कि, स्कूल में छात्रा के साथ बेड टच का मामला उनके संज्ञान में है। सूचना मिलने के बाद शनिवार को वे और जिले का स्टाफ स्कूल पहुंचा था। उसी समय गेस्ट टीचर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वह क्लास-1 श्रेणी का गेस्ट टीचर था। सरकार उसे प्रति महीने 18 हजार रुपए का मानदेय देती थी।

एसपी बोले- आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया: एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि, अतिथि शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलते ही खालवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल की अन्य छात्राओं से बात की जाएगी। किसी छात्रा ने पूर्व में शिकायत की होगी तो रिकॉर्ड देखा जाएगा। जानकारी मिली है कि संबंधित विभाग ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई की है।

एम्स भोपाल में राष्ट्रीय पैथोलॉजी क्रिज 2024 का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन विभाग द्वारा शुक्रवार को आईएपीएम राष्ट्रीय पैथोलॉजी क्रिज 2024 के फाइनल राउंड का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देशभर के प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रों को एक मंच पर लाने और उनके ज्ञान और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने का साक्षी बना। यह क्रिज भारतीय पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट संघ की एक प्रमुख पहल है। इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड 20 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें देशभर से 12 टीमों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के शीर्ष पांच टीमों को फाइनल राउंड के लिए चुना गया।



फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे एम्स भोपाल की सुश्री झलक शाह और श्री तेजस मोहाले को विजेता घोषित किया गया। जम्मू-कश्मीर की सुश्री दिया टिक्कू और श्री कार्तिक भट प्रथम उपविजेता और केरल की सुश्री नर्तनारा और सुश्री अंजू द्वितीय उपविजेता रहीं। शीर्ष तीन

–आईएपीएम राष्ट्रीय पैथोलॉजी क्रिज हमारे देश में शैक्षणिक उत्कृष्टता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। इस तरह के आयोजन न केवल युवा दिमागों की बौद्धिक क्षमता को निखारते हैं बल्कि टीम वर्क और नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं।–

कार्यक्रम की मुख्य समन्वयक और एम्स भोपाल के पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन विभाग की प्रमुख, प्रो. वैशाली वल्के ने विजेताओं को बधाई दी और अपनी टीम के संकाय सदस्यों प्रो. दीप्ति जोशी, प्रो. अश्वनी टंडन, प्रो. गरिमा गोयल, डॉ. ई. जयशंकर, डॉ. तान्या शर्मा, और डॉ. जय चौरसिया तथा सभी रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इस समारोह में डीन (अकादमिक) प्रो. रजनीश जोशी और एनाटॉमी विभाग की प्रमुख, प्रो. बर्था रंथनम भी उपस्थित रहे।

भाजपा ने किया बूथ समितियों का गठन और डिजिटलाइजेशन, संगठन एवं इतिहास रचेंगे पार्टी कार्यकर्ता

राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं की सराहना कर दी बधाई : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल (नप्र)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश में सभी बूथ समितियों के गठन और सभी बूथों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो जाने पर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संगठन पर्व के दौरान प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता नया इतिहास रचने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने संगठन पर्व में कठिन परिश्रम कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश में 2 सितम्बर और मध्यप्रदेश में 3 सितम्बर से पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी। शुरुआत से ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। चाहे प्राथमिक सदस्यता की बात हो या सक्रिय सदस्यता की, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर बार लक्ष्य से अधिक काम किया है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों ने पूरी गुणवत्ता और संपूर्णता के साथ समय सीमा में 100 प्रतिशत बूथ समितियों के गठन की संभव कर दिखाया। ये समितियां सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी हैं। इनमें सभी जाति, वर्ग और आयु समूह के लोगों को शामिल किया गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि महिला सशक्तीकरण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में योगदान देते हुए बूथ समितियों में भी 33 प्रतिशत महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि बूथ समितियों के गठन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने तमाम परेशानियों के बावजूद 100 प्रतिशत बूथ समितियों के डिजिटलाइजेशन को भी पूरा कर दिखाया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पार्टी कार्यकर्ताओं के इन प्रयासों और परिश्रम की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी सराहना की है और उन्हें बधाई दी है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संगठन पर्व अभी जारी है। इस दौरान विभिन्न नवाचारों के जरिए संगठन के रचनात्मक कार्यों को धरातल पर उतारकर हमारे संगठन ने आदर्श स्थापित किए हैं।

वैष्णव भक्तों ने इटारसी जाकर हरिनाम संकीर्तन किया..

नर्मदापुरम। एलआईसी दफ्तर के उपर द्वितीय तल स्थित इस्कॉन मंदिर परिवार ने आज इटारसी जाकर वहां मेहराणांव में हरिनाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण भक्ति के प्रचार-प्रसार में नर्मदापुरम इस्कॉन मंदिर परिवार अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी की इच्छानुरूप बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहा , प्रति रविवार को सुबह मंदिर परिवार के वैष्णव और भक्त समीपस्थ ग्रामों में पहुंचकर गांव में हरिनाम संकीर्तन कर भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे उस क्रम में आज मंदिर प्रभुएं प्रणव दास प्रभु की अगुवाई में इटारसी स्थित मेहराणांव पहुंचकर भक्तों ने गांव में हरिनाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण भक्ति प्रचार के साथ ही साथ पुस्तक वितरण का कार्य भी किया। हरिनाम संकीर्तन के उपरांत मंदिर प्रमुख श्री मान प्रणव दास प्रभु ने मेहराणांव स्थित बड़े मंदिर में यथारूप श्रीमद्भगवद्गीता पर प्रवचन किया।



राइट क्लिक

आत्मनिरीक्षण: क्या कांग्रेस में सचमुच कोई आमूल बदलाव होगा?



अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के
कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क:-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

पहले हरियाणा व अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों परिणामों से हैरान और उड़ेलित कांग्रेस पार्टी अगर सचमुच गंभीर आत्मनिरीक्षण और संगठनात्मक ढांचे में आमूल सुधार करने जा रही है तो इससे अच्छी कोई बात पार्टी और देश के लिए हो नहीं सकती। महाराष्ट्र व हरियाणा में इस बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही कांग्रेस की दयनीय पराजय के बाद दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ खरी खरी बातें कही। लेकिन ये तमाम बातें व्यावहारिक अंजाम तक भी पहुंचेंगी, यह खरगे भी नहीं जानते। खरगे ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा, माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं है। इस पर बैठक में मौजूद पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने खरगे से कहा कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लें। यहीं सबसे बड़ा पेंच है ? कि क्या खरगे सचमुच कोई कठोर एक्शन लेने की स्थिति में हैं? क्या उनके पास व्यवहार में ऐसे अधिकार हैं? वो अगर एक्शन लेंगे भी तो किनके खिलाफ लेंगे? दूसरे, बैठक में पार्टी को कसने को जो नेक सुझाव खरगे ने दिए, उन पर पहले ही अमल करने से उन्हें किसने रोका था? यह आत्मज्ञान उन्हें अभी क्यों हुआ? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो वो दो साल से हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की मूल समस्या ही ये है कि उसका सिर से पैर तक संगठनात्मक ढांचा चरमराया हुआ है। खासकर 2014 के बाद तो उसकी स्थिति और भी बदतर होती गई है। हर चुनावी हार के बाद यह बात उठती है कि पार्टी संगठन में सुधार जरूरी है। लेकिन हकीकत में सुधार के लिए कुछ नहीं होता है। होता भी है तो दिखावे के लिए। उसमें भी किसी राज्य, कुछ लोकसभा सीटों या स्थानीय निकायों के चुनावों में मिली

क्षणिक सफलताएं पार्टी की आंतरिक कलह और अंतर्विरोधों को फिर कालीन के नीचे सरका देती हैं। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में आत्मालोचन की कोशिशें हुईं। कुछ सच्चाई बयान भी की गईं। लेकिन इसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर कुछ ठोस होगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि समय पर निर्णय न होना, अवसर चूक जाने के बाद फैसले होना, फैसलों में भी जमीनी हकीकत और जरूरत को ध्यान में रखने की जगह व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों का हावी होना, अंतर्कलह पर काबू न होना, गुटीय संतुलन में वक्र जाया होना, शीर्ष नेताओं का चंद चेहरों से घिरा होना, परिणामों के बाद की संभावित स्थिति के मद्देनजर अपना वर्चस्व में कायम रखने की जोड़ तोड़ करना, हर बात में हाई कमान के भरोसे रहना, जमीन पर काम करने की जगह आला कमान का कृपापात्र बनने की होड़ कायम रहना, जमीनी कार्यकर्ता की केवल चुनाव के समय पूछ परख होना, चुनाव जीतने , काल परिस्थिति और स्थानीय जरूरत के हिसाब रणनीति बनाने और तदनुसार मुद्दे उठा सकने में विफल रहना, स्पष्ट वैचारिक सोच न होना, संगठन को सतत निरंतर राजनीतिक काम में व्यस्त न रख पाना, सचबयानी करने वाले चंद चेहरो को खारिज करना, कभी क्षेत्रीय दलों की तरह व्यवहार करना तो कभी खुद को राष्ट्रीय पार्टी की तरह पेश करना ऐसी पुरानी और गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज पार्टी आज तक नहीं खोज पाई है। बहरहाल सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने कुछ अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि खड़गे ने कहा कि राज्य चुनावों में उम्मीद से कम प्रदर्शन हमारे लिए चुनौती है। पार्टी नेताओं में एकता की कमी, एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चुनावों में हमें नुकसान पहुंचा रही है, इस पर सख्त अनुशासन की जरूरत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाने होंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव का माहौल हमारे पक्ष में होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती। समयबद्ध रणनीति

बनाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विधानसभा चुनावों के लिए एक साल पहले से तैयारी करनी होगी, मतदाता सूचियों की जांच करनी होगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश भर में लोगों के एजेंडे को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव नतीजों ने हमें झकझोर दिया, हमें कड़े कदम उठाने होंगे। जहां तक पार्टी में सुधार की बात है तो यह मुद्दा कई बार उठा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी की अगुवाई में कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में हार के कई कारण बताए। वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन बताया जाता है कि रिपोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में एक शब्द नहीं कहा या ऐसा कर सकने का साहस उसमें नहीं था। जबकि पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में हारी थी। उसी साल हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की हार के बाद 2016 में पार्टी के तत्कालीन महासचिव दिग्विजयसिंह ने पार्टी में मेजर सर्जरी की जरूरत बताई थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पार्टी का ढरा जैसा चल रहा था, चलता रहा। लेकिन 2024 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया तो क्रेडिट राहुल गांधी को दी गई, जबकि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं। ऐसे में खड़गे कितनी दमदारी से एक्शन ले पाएंगे, यह समझा जा सकता है। बैठक में दूसरा अहम मुद्दा ईवीएम का रहा। हर हार के बाद कांग्रेस का विश्वास इस मशीन से उठने लगता है तो जीतने पर वह ईवीएम के नतीजों को वास्तविक जनादेश बताने लगती है। खरगे ने भी कहा कि ईवीएम ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन ईवीएम को लेकर यह प्रश्नचिह्न केवल महाराष्ट्र

विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर ही है। इसमें पिछले दिनों हुए हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना अथवा कर्नाटक राज्य के विस चुनाव शामिल नहीं हैं और न ही लोकसभा में महाराष्ट्र व यूपी आदि राज्यों के नतीजों पर सवालिया निशान है। यह भी खास बात है कि ईवीएम की बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी कर रही कांग्रेस उसके द्वारा शासित राज्यों में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव भी बैलेट पेपर से नहीं कराती। मसलन हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार वजूद में आने के ?बाद शिमला नगर निगम के चुनाव ईवीएम से हुए। उसमें कांग्रेस जीती तो किसी को ईवीएम में कोई खोट नजर नहीं आई। अगर पार्टी का ईवीएम से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है तो उसके द्वारा शासित राज्यों के राज्य चुनाव आयोगो को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या अड़चन है? अब पार्टी महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर जन आंदोलन करने जा रही है। इसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लिया जाएगा। आंदोलन केवल महाराष्ट्र में इसलिए है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, जम्मू काश्मीर आदि राज्यों की सरकारों को ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। इस आंदोलन को जनता को कितना समर्थन मिलेगा, यह देखने की बात है। क्योंकि राजनीतिक अपने चश्मों से हिसाब से कुछ भी देखें, आम मतदाता को पता होता है कि उसने किसको वोट दिया है और क्यों दिया है ? वैसे ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस में एकमत नहीं है। पी. चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव नहीं है। यह बात इसलिए भी सही लगती है कि चुनाव अब केवल चुनाव सभाओंमें लुभावनी या लच्छेदार बातों से नहीं जीते जाते, बुध मैनेजमेंट और अपने वोट हर हाल में डलवा सकने वाली पार्टी के मशीनरी के जरिए जीते जाते हैं। अगर माहौल पार्टी के पक्ष में हो तो भी यदि उसी अनुपात में वोट नहीं गिरे तो इस खाम खयाली का कोई मतलब नहीं है।



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन-पूजन व अभिषेक कर आशीर्वाद लिया।

सिंधिया बोले- मैं बयान के बयान में नहीं लगता

भाजपा संगठन के सवाल को टाला, पार्टी ने कहा था- उन्हें चुनाव प्रचार में बुलाया गया था



गुना (नप्र)। विजयपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के न जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा संगठन ने कहा कि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वह व्यस्तता के कारण नहीं गए। प्रदेश महामंत्री के इस बयान पर सिंधिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुना में कहा कि वह बयान पर बयान नहीं देते। बता दें कि जब सिंधिया

भगवानदास सबनानी ने कहा- विजयपुर के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम था। सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने उन्हें विजयपुर में आने के लिए आग्रह किया था। सिंधिया ने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था। उनको आमंत्रित किया गया था। शनिवार देर रात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। रविवार सुबह उनसे जब भगवानदास सबनानी के बयान पर सवाल पूछा गया तो सिंधिया ने कहा कि मैं बयान के बयान में नहीं लगता।

कहीं-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सुजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

छत्तीसगढ़ में अभी दो मंत्री पद खाली हैं। एक तो बुजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे से रिक्त हुआ। एक पद शुरू से खाली है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि राज्य में मंत्री के दो पद कब तक खाली रहेंगे। हरियाणा का फार्मुला लागू किया गया, तो तीन नए मंत्री बन सकते हैं। 90 विधानसभा वाले हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में 13 का फार्मुला है। राज्य में कई विधायक मंत्री बनने की कतार में हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद लोगों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। राजधानी से विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रायपुर के किसी एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पहले राजेश मृगत का नाम चर्चा में था। अब सुनील सोनी का नाम आगे आने लगा है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी दौड़ में बताए जाते हैं। बस्तर से अभी केदार कश्यप मंत्री हैं। वहां से लता उसेंडी और किरण सिंह देव का नाम चर्चा में है। लता बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं। किरण सिंह देव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री के अलावा दो मंत्री हैं, पर वहां से रेणुका सिंह को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। रेणुका सिंह मोदी 2 में केंद्रीय राज्य मंत्री थीं। मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर

छत्तीसगढ़: कब तक खाली रहेंगे सरकार में मंत्री पद

उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। बिलासपुर संभाग से उपमुख्यमंत्री अरुण साव हैं, फिर भी नए मंत्री के लिए अमर अग्रवाल का नाम सुर्खियों में है। महासमृद्ध लोकसभा से साय मंत्रिमंडल में अभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां से प्रतिनिधित्व के लिए अजय चंद्राकर आगे चल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ निगम-मंडलों में राजनेताओं की नियुक्ति भी अटकती है। साय सरकार निगम-मंडलों में छिटपुट नियुक्ति कर रही है, लेकिन लोगों को थोक नियुक्ति का इंतजार है। दिसंबर में सरकार को एक साल पूरे हो जाएगा। ऐसे में निगम -मंडलों में बैठने वाले नेताओं को चार साल सत्ता सुख का आनंद लेने का मौका मिलेगा।

अशोक जुनेजा फिर एक्सटेंशन के फिराक में ?

खबर है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने नए डीजीपी के लिए पांच अफसरों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है। इस बीच फिर चर्चा चल पड़ी है कि डीजीपी अशोक जुनेजा और छह माह एक्सटेंशन के लिए जुगाड़-गुगाड़ में लगा गए हैं। श्री जुनेजा अभी सेवावृद्धि में हैं और उनका कार्यकाल पांच फरवरी 2025 तक है। कहते हैं श्री जुनेजा की सेवावृद्धि के लिए भारत सरकार में कुछ महीने पहले तक काफी पावरफुल रहे एक रिटायर्ड अफसर लांबिंग कर रहे हैं। बताते हैं लांबिंग करने वाले रिटायर्ड अफसर को कई बार मोदी सरकार में एक्सटेंशन मिला था। कहा जा रहा है कि अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन दोबारा मिलता है, तो फिर अरुणदेव

गौतम,पवनदेव और हिमांशु गुप्ता पीछे रह जाएंगे। तीनों डीजी स्तर के अधिकारी हैं। बताते हैं राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए इन तीनों अफसरों के अलावा एडीजी प्रदीप गुप्ता और एडीजी एसआरपी कछूरी का नाम पैनल में यूपीएससी को भेजा है।

सुर्खियों में वन विभाग

छत्तीसगढ़ का वन विभाग इन दिनों अपने कुछ छलिया टाइप के अधिकारियों -कर्मचारियों के चलते सुर्खियों में है। एक महिला रेंजर ने एक डीएफओ पर प्रताड़ना और बुरी नीयत रखने का आरोप लगाया है। यह मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। बताते हैं महिला रेंजर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दफ्तर से लेकर ट्राइबल कमीशन तक शिकायत कर दी है। दिल फेंक आदर और झंझा देने के आरोप में एक रेंजर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो एक चौकीदार भी एक महिला को झंझा देने के फेर में उलझ गया है। चर्चा का विषय है कि वनों और जीव-जंतुओं की रक्षा और प्रेम करने वाले कैसे रास्ता भटक गए और विभाग को सुर्खियों में ला दिए ।

बाजी मार गया मुख्यमंत्री का विभाग

कहते हैं कि नया रायपुर में नए प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विभाग बाजी मार गया। खबर है कि मुख्यमंत्री के मातहत काम करने वाला संस्कृति और पर्यटन विभाग भारत सरकार से मंजूरी लेकर नया प्रोजेक्ट लॉच

कर दिया। इसमें एक फिल्म सिटी भी है। दूसरे विभाग पीछे रह गए। बताते है दो विभाग नया रायपुर में नए प्रोजेक्ट के लिए लगे थे, पर उनका काम आगे नहीं बढ़ पाया। कहा जा रहा है कि पर्यटन और संस्कृति विभाग के अफसर प्रोएक्टिव होकर भारत सरकार के अफसरों से तालमेल बैठाया और अपना काम करा लिया। चर्चा है कि पीछे रह गए दोनों विभाग के अफसर भी अब भारत सरकार से लिंक तलाश करने में लग गए हैं।

भाजपा राज में एक कांग्रेस नेता के जलवे

कहते हैं भाजपा राज में भी कांग्रेस के एक नेता के इन दिनों जलवे हैं और काम-धंधा भी शबाब पर है। बस्तर इलाके के कांग्रेसी नेता का पिछली सरकार में अपनी पार्टी के ही एक नेता से विवाद सुर्खियों में था। इस बार कांग्रेस नेता ने भाजपा राज में एक पावरफुल आदमी को पकड़ा और अपनी नैय्ता पार करवा ली। भाजपा राज के पावरफुल व्यक्ति को एक मंत्री का करीबी बताया जाता है। बताते हैं कांग्रेस नेता से उस व्यक्ति के गठजोड़ का पता चलने के बाद भाजपा के कुछ लोगों ने नजरें टेढ़ी की, पर कांग्रेस नेता का बाल बांका नहीं हुआ।

बिल्डर का नेता- अफसरों से गठजोड़ की चर्चा

राजधानी के एक बिल्डर को अमलीडीह का कई एकड़ सरकारी जमीन आबंटित करने के बाद नेता-अफसरों से उसके गठजोड़ की चर्चा होने लगी है। सवाल

उठ रहा है कि कालेज के लिए आरक्षित सरकारी जमीन आखिर कैसे बिल्डर को आबंटित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बिल्डर द्वारा विकसित कालोनी में कई अफसर और नेताओं ने बंगले ले रखे हैं। कुछ नेता और अफसरों तो अभी बिल्डर की कालोनी में रहते हैं। बताते हैं एक मंत्री के अलावा वर्तमान में मंत्रालय में पदस्थ कुछ अफसर बिल्डर की कालोनी में रहते भी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिल्डर की कालोनी में रहने वाले अफसर सरकारी बंगले छोड़कर प्राइवेट बंगलों में क्यों रहते हैं? लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि आरखीए और हाउसिंग बोर्ड की कालोनी छोड़कर अफसरों ने प्राइवेट बिल्डर के बंगलों को प्राथमिकता क्यों दी ? सरकार ने अफसरों के लिए पुराने के साथ नया रायपुर में भी बड़े-बड़े बंगले बनवा रखी है। नया रायपुर के बंगलों में कुछ अफसरों ने रहना भी शुरू कर दिया है।

अमित कटारिया को पोस्टिंग का इंतजार

2004 बैच के आईएएस अमित कटारिया छुट्टी से लौटकर मंत्रालय में ज्वाइनिंग दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग में आमद दिए करीब एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अमित कटारिया को कोई विभाग नहीं मिला है। लोगों को अमित कटारिया के पोस्टिंग का इंतजार है। अमित कटारिया लंबे समय तक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में रहने के बाद करीब दो महीने पहले छत्तीसगढ़ लौटे। माना जा रहा है कि अमित कटारिया की पोस्टिंग के साथ मंत्रालय में अफसरों के विभागों में छौटा हेरफेर हो सकता है।

